Bengaluru, one of the seven cities chosen under the Smart Cities Mission in Karnataka, continues to grapple with severe traffic issues and infrastructural shortcomings. City's traffic woes still persist, exacerbated by seasonal factors such as rain, inadequate public transportation network, and persistent civic issues collectively impede Bengaluru's progression as a 'smart city.' Recent incidents such as the tragic death of a 23-year old woman and her infant due to an unattended live wire on a footpath underscore the urgent need for comprehensive action. Another distressing incident occurred in May, 2022, where a young professional lost her life as her car got trapped in the flooded underpass. Furthermore, residents in flood-prone areas have attributed waterlogging and flooding issues to the smart city projects. These unfortunate events serve as reminders of the pressing infrastructural challenges being faced by Bengaluru.

I earnestly urge the Government to collaborate closely with the local municipal body to address the concerns, ensure safety and well-being of the citizens, and take immediate steps to translate the Smart Cities Mission into tangible improvements that positively impact the lives of Bengaluru's residents. The focus should be on enhancing the quality of life, mitigating civic issues, and ultimately restoring Bengaluru's status as a global city of the future.

Demand for CGHS Wellness Centre in Kangara, Himachal Pradesh.

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में CGHS वैलनेस केन्द्र की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर व जिला चंबा में CGHS के अंतर्गत इलाज कराने वाले लोगों को चंडीगढ़ व शिमला जाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इन जिलों से आवागमन में बहुत समय लगता है। प्रायः बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों को इलाज के लिए एक अटेंडेंट के साथ रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिला कांगड़ा से हमीरपुर 90 किलोमीटर है तथा जिला चंबा 120 किलोमीटर है, इसलिए आम जन एक दिन में ही आना-जाना कर सकते हैं।

जिला कांगड़ा में लगभग 20 से ज्यादा केन्द्र सरकार के कार्यालय हैं, जिनमें लगभग दस हजार से अधिक CGHS का लाभ लेने वाले केन्द्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा आर्मी व अन्य पैरा मिलिट्री फोर्स में सेवा दे रहे जवान व उनके परिवार के सदस्य भी रहते हैं, जिनमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है।

महोदय, इन जिलों में लगभग हर घर का एक सदस्य आर्मी या पैरा मिलिट्री फोर्स में कार्यरत है। पालमपुर और धर्मशाला कैंटोनमेंट क्षेत्र भी है, जहां काफी संख्या में सेना के जवान व उनके परिवार के सदस्य रहते हैं, उनके लिए भी CGHS की सुविधा लेना आसान हो जाएगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के मद्देनज़र जिला कांगड़ा में CGHS वेलनेस सेंटर बनाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

Concern over production capability and high price of ethanol

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): महोदय, सरकार के द्वारा 2025 तक 20 परसेंट ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत होगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को प्राप्त करने के प्रयास की सफलता में प्रमुख समस्या पर्याप्त इथेनॉल का प्रोडक्शन, रॉ मैटेरियल की उपलब्धता, उपयुक्त तकनीक तथा निवेश एवं इथेनॉल के दामों को सभी स्टेकहोल्डर्स के हित में तय करना है। ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल 1,350 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान दाम, इंसेंटिव और निवेश से संभव नहीं है। लगातार इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इथेनॉल के लिए विभिन्न विकल्पों को लेकर चलना होगा। शुगर से प्राप्त इथेनॉल के लिए शुगर मिल्स को वित्तीय मजबूती देनी होगी एवं अधिक से अधिक शुगर को इथेनॉल के लिए डायवर्ट करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक इंसेंटिव देने की जरूरत है। देश में इथेनॉल प्रोडक्शन प्रारंभिक अवस्था में है, जिसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। सरकार को शुगर से प्राप्त इथेनॉल के दामों में कम से कम 7-9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इथेनॉल के दामों को आकर्षक बनाकर इथेनॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने से बहुउद्देशीय इथेनॉल नीति का समग्र रूप से देश को लाभ मिलेगा। एक अच्छी इथेनॉल पॉलिसी से धरातल पर एक मजबूत इथेनॉल इंडस्ट्री की स्थापना में इथेनॉल के दामों का सही निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार उचित कदम उठाएगी।

Concern over Jangam Community in Northern India

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा) : महोदय, उत्तर भारत के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों में जंगम जाति सदियों से घंटी-भिक्षा करके जीवनयापन कर रही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं : -

1. उपरोक्त राज्यों में जंगम जाति की कुल जनसंख्या मात्र 58,000 है। शत-प्रतिशत भूमिहीन व अशिक्षित होने के कारण केवल मात्र 0.001% व्यक्ति ही सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करते हैं।
2. उत्तर भारतीय राज्यों में जंगम जाति सदियों से घंटी-भिक्षा द्वारा शिव गायन करके जीवनयापन कर रही है।
3. माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा स्थापित इदायते आयोग की रिपोर्ट में भी हरियाणा व राजस्थान की जंगम जाति को घूमंतु जाति (Nomadic Tribes) घोषित किया गया है।
4. विश्व संस्था यूनेस्को (UNESCO) द्वारा हरियाणा में जंगम जाति की बहुत कम जनसंख्या होने के कारण वर्ष 2011 में जंगम परम्परा को लुप्तप्रायः घोषित किया गया है।